पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

डिजिटल शिक्षा को घर–घर पहुंचा रही योगी सरकार, पीएम ई–विद्या पर एक मंच में मिलेंगे पढ़ाई के जरूरी संसाधन

एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे संसाधन, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है ऐप

लखनऊ : 10 सितंबर, 2026

योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल को लगातार विस्तार दे रही है। सरकार का जोर है कि डिजिटल संसाधन विद्यार्थियों की पहुंच से दूर रहने वाली सुविधा न होकर सीखने का सहज, सुलभ और प्रभावी माध्यम बनें। इसी दिशा में पीएम ई–विद्या डिजिटल प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन एक ही मंच पर निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। पीएम ई–विद्या जैसे प्लेटफॉर्म सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और प्रभावी बनाते हैं।

महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि डिजिटल संसाधनों की आसान और निःशुल्क उपलब्धता सीखने और सिखाने के नए अवसर खोलती है। एससीईआरटी स्तर पर हमारा प्रयास है कि इन संसाधनों का विद्यालयी शिक्षण में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो।

एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान के मुताबिक, पीएम ई–विद्या के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने और उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। एक ही मंच पर सामग्री उपलब्ध होने से डिजिटल शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी पीएम ई–विद्या ऐप के बारे में जानकारी साझा की जा रही है।

एक मंच पर जरूरी संसाधन, निःशुल्क उपलब्ध

पीएम ई–विद्या में पढ़ाई से जुड़े आवश्यक डिजिटल संसाधनों तक एक ही स्थान से पहुंच की सुविधा है, जिससे अलग–अलग माध्यमों पर निर्भरता कम होगी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी संसाधन निःशुल्क उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा से अध्ययन कर सकते हैं और शिक्षक भी इसे कक्षा शिक्षण के सहयोगी माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

पीएम ई–विद्या ऐप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर तथा आईओएस उपयोगकर्ता एप्पल ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

वैशाली माथुर / 11:58 AM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in

योगी सरकार में हर कक्षा को मिलेगा सीखने का नया साधन, ₹56.36 करोड़ से बनेंगे टीएलएम

कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षण–अधिगम सामग्री निर्माण के लिए बजट जारी, 15 अक्टूबर तक खरीद और 31 अक्टूबर तक निर्माण

लखनऊ : 10 सितंबर, 2026

योगी सरकार बेसिक शिक्षा में कक्षा–कक्ष को अधिक प्रभावी और गतिविधि आधारित बनाने के लिए विद्यालयों में शिक्षण–अधिगम सामग्री (टीएलएम) की उपलब्धता को सुदृढ़ कर रही है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2026–27 में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा टीएलएम तैयार करने के लिए ₹56.36 करोड़ का बजट जारी किया गया है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों को टीएलएम निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे संसाधन कक्षा–कक्ष को अधिक जीवंत और सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाएंगे। इसमें बच्चों की सहभागिता से रचनात्मकता भी विकसित होगी।

महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि टीएलएम का उपयोग बच्चों की सीखने की जरूरतों के अनुरूप हो और उत्कृष्ट नवाचारों को मेले के माध्यम से व्यापक स्तर पर साझा किया जाए।

राज्य परियोजना निदेशक एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में जिलों को धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 अक्टूबर तक खरीद, 31 अक्टूबर तक निर्माण, लगेगा टीएलएम मेला

निर्देशों के अनुसार सामग्री की खरीद 15 अक्टूबर 2026 तक पूरी करनी होगी, जबकि शिक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर 2026 तक कक्षावार एवं विषयवार टीएलएम तैयार किया जाएगा। उत्कृष्ट और नवाचारी सामग्री को सामने लाने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर पर 'निपुण टीएलएम मेला उत्सव' आयोजित होगा, जिसमें शिक्षकों द्वारा विकसित टीएलएम का प्रदर्शन और कक्षा में उसके प्रभावी उपयोग का प्रस्तुतीकरण होगा।

हर कक्षा की जरूरत के अनुरूप सामग्री

यह बजट निपुण लक्ष्य के अनुरूप विषयवार और कक्षावार टीएलएम तैयार करने के लिए है। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 'निपुण लक्ष्य' पोस्टर, गणित एवं हिंदी की तालिका, कक्षा 3 से 5 के लिए अंग्रेजी एवं पर्यावरण अध्ययन की तालिका, आईईसी सामग्री, कैच–अप शिक्षण एवं आकलन ट्रैकर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्ड बोर्ड, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, एबेकस, ग्लोब, भारत एवं विश्व के मानचित्र, कठपुतलियां, पशु–पक्षियों के चार्ट, घड़ी, वर्णमाला कार्ड आदि सामग्री की व्यवस्था सुझाई गई है। टीएलएम पाठ्य बिंदु और शिक्षण योजना के अनुरूप, टिकाऊ और उपयोगी होगा तथा बच्चों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल टीएलएम निर्माण में ही होगा। सामान्य स्टेशनरी, सफाई सामग्री, सजावट या व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं किया जाएगा। निगरानी प्रधानाध्यापक, बीईओ, बीएसए, डायट एवं शैक्षिक टीमों द्वारा की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

वैशाली माथुर / 11:58 **AM**

पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

बच्चों की पढ़ाई में अभिभावक बनेंगे भागीदार, डीबीटी की मदद से संवरेंगी उनकी जरूरी सुविधाएं

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए डीबीटी राशि का उपयोग केवल स्कूल ड्रेस, जूता–मोजा, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी पर ही होगा

लखनऊ : 10 सितंबर, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के साथ अभिभावकों की सहभागिता को भी मजबूत कर रही है। इसी क्रम में शैक्षिक सत्र 2026–27 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ड्रेस, जूता–मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से दी जा रही धनराशि के निर्धारित उद्देश्य में ही उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि डीबीटी धनराशि का निर्धारित सामग्री पर उपयोग होने से बच्चों की शैक्षिक जरूरतें पूरी होंगी और विद्यालय के प्रति उनका जुड़ाव मजबूत होगा।

महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि डीबीटी राशि के निर्धारित उपयोग और सामग्री की पहुंच का विद्यालय स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित कराया जा रहा है। सामग्री के नियमित उपयोग और संरक्षण के लिए जागरूक करने पर विशेष जोर है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके व्यापक प्रचार–प्रसार और प्रभावी अनुपालन के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने कहा है कि डीबीटी की धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित सामग्री की खरीद में ही किया जाए। अभिभावकों को ऐसी सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता पूरे सत्र बनी रहे और बच्चे नियमित उपयोग कर सकें। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अभिभावकों से संवाद कर यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे विद्यालय में सामग्री का नियमित उपयोग कर रहे हैं।

विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को प्राप्त सामग्री का कक्षावार एवं छात्रवार सत्यापन कराया जाएगा। यह देखा जाएगा कि बच्चे ड्रेस, जूता–मोजा, स्वेटर में विद्यालय आ रहे हैं और बैग व स्टेशनरी का उपयोग कर रहे हैं। अभिभावकों को ड्रेस का उपयोग मुख्य रूप से विद्यालय एवं विद्यालयीय गतिविधियों में करने और सामग्री के नियमित रखरखाव के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि डीबीटी राशि का अन्य मदों में खर्च नहीं किया जाना है। उल्लंघन की जानकारी मिलने पर अभिभावकों से संपर्क कर परामर्श दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी निरीक्षण के दौरान इसकी निगरानी करेंगे।

सम्पर्क सूत्र– धर्मवीर खरे

वैशाली माथुर / 11:58 **AM**

वर्ल्ड इंक्लूज़न कॉन्फ्रेंस की सीख को विभागीय कार्यों में उतारने पर हुआ मंथन

राज्य मंत्री असीम अरुण की मौजूदगी में अधिकारियों ने साझा किए अनुभव और दिए नवाचार के सुझाव

लखनऊ : 10 सितम्बर, 2026

नई दिल्ली में हुए वर्ल्ड इंक्लूज़न कॉन्फ्रेंस–2026 से मिली सीख अब समाज कल्याण विभाग के कामकाज में नई सोच और नए प्रयासों का आधार बनेगी। इसी उद्देश्य से बुधवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में बैठक आयोजित की गई। "एक विश्व, सबका सम्मान" थीम पर हुई इस बैठक में समाज कल्याण राज्यमंत्री श्री असीम अरुण, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक श्री आशीष, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री अनुराग यादव और निदेशक श्री संजीव सिंह समेत सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नई जरूरतों के अनुरूप नीतियों पर विचार

कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने वाले नव नियुक्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने अनुभव और सीख साझा की। बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया कि समाज कल्याण के क्षेत्र में उभरती नई जरूरतों की पहचान कर उनके अनुरूप नई नीतियों और प्रभावी कार्यक्रमों की दिशा में किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। अधिकारियों ने अपने अनुभवों के आधार पर नवाचार और समाधान आधारित दृष्टिकोण अपनाने की संभावनाएं साझा कीं।

"नई सोच के साथ नीतियां बनाने पर दें जोर'

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में प्राप्त अनुभवों को केवल व्यक्तिगत सीख तक सीमित न रखते हुए नई सोच के साथ विभागीय कार्यों में ठोस बदलाव और बेहतर नीतियों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से समाज कल्याण के क्षेत्र में नई आवश्यकताओं की पहचान कर नवाचार और समाधान आधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

वैशाली माथुर/11:58 **AM**

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

सीतापुर में मिड–डे मील का राशन न पहुंचाने के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश

परिवहन ठेकेदार पर एफआईआर, फर्म होगी ब्लैक लिस्ट; लापरवाह अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही–खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय

लखनऊ : 10 सितम्बर, 2026

जनपद सीतापुर में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन ठेकेदार द्वारा मिड–डे मील का राशन संबंधित उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) तक न पहुंचाए जाने के गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कड़ा रुख अपनाया है।

मंत्री श्री पाण्डेय ने जिलाधिकारी, सीतापुर को संबंधित परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराने तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रकरण में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

श्री पाण्डेय ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप भ्रष्टाचार, लापरवाही अथवा शासकीय खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "जनता और बच्चों के हक के राशन में गड़बड़ी अत्यंत गंभीर विषय है। खाद्यान्न निर्धारित स्थान तक समय से पहुंचाना संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित अनुश्रवण के भी निर्देश दिए हैं।

सम्पर्क सूत्र– अखिलेश पाण्डेय

राघवेन्द्र / 03:15 PM

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में प्रदेश के सेनानियों के ऐतिहासिक स्थलों की बनेगी सर्किट, आजादी की गाथा और पर्यटन का होगा नया आकर्षण

लखनऊ : 10 सितम्बर, 2026

मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़कर नई पहचान देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के अलग–अलग जिलों में उन स्थानों का पर्यटन विकास कराया जा रहा है, जहां स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और वीर सेनानियों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी।

मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग का उद्देश्य इन स्थलों को केवल स्मारकों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करना है, जहां आने वाले पर्यटक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को करीब से जान सकें और महसूस कर सकें। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी, वे–फाइंडिंग, सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं और इतिहास की जानकारी देने वाले व्याख्या केंद्रों पर जोर दिया जा रहा है।

प्रदेश के वाराणसी पिण्डरा क्षेत्र के करखियांव गांव में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल का पर्यटन विकास कराया जा रहा है। परियोजना के लिए 18.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 8 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। गांव, में शहीद हुए 26 लोगों की स्मृति में यहां एक म्यूरल पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी वीरगाथाओं को म्यूरल के माध्यम से उकेरा जाएगा। रायबरेली सदर क्षेत्र तहसील ऊंचाहार के मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक स्थल का 4.51 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास का कार्य कराया जा रहा है। परियोजना का करीब 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। यह स्थल क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों की स्मृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लखनऊ जनपद के उमरिया मजरे मुसपिपरी गांव में अमर शहीद राजा दिग्विजय सिंह स्मारक का पर्यटन विकास का कार्य कराया जा रहा है। परियोजना के लिए करीब 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 55 लाख रुपये जारी हो चुके हैं। स्मारक के विकास से स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को नई पहचान मिलेगी।

औरैया जनपद के मुख्यालय स्थित ककोर तिरंगा पार्क, मैदान का जिला योजना के तहत पर्यटन विकास कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और राष्ट्रध्वज से जुड़ी भावनाओं को नई पीढ़ी से जोड़ते हुए स्थल को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। बलिया में सिताबदियारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान और राष्ट्र निर्माण की भूमिका को देखते हुए उनके गांव में पर्यटन विकास के माध्यम से उनकी विरासत को संरक्षित

और प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी क्रम में सेवादास धाम मंदिर का भी पर्यटन के दृष्टिगत विकास कराया जा रहा है।

शाहजहांपुर जनपद के पुवायां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जसवंतपुर में शहीद करतम सिंह पार्क का 79 लाख रुपये की लागत से निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। इस पार्क को शहीद की स्मृति को संजोने के साथ–साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित किया गया है। हरदोई ग्राम सेमरिया स्थित शहीद स्थल का 41 लाख रुपये की लागत से पर्यटन के रूप में विकास कराया गया है। विकास कार्यों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन से जुड़ी स्थानीय स्मृतियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

जनपद बलिया स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के नायक मंगल पाण्डेय से जुड़े स्मारक स्थल का 1.55 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण कराया गया है। इससे बलिया की स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत को पर्यटन से जोड़ने में मदद मिलेगी। बलिया जनपद के बांसडीह में वीर कुंवर सिंह के नाम पर शहीद स्मारक का निर्माण एवं पर्यटन विकास का कार्य 86 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। यह स्थल स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों की स्मृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

प्रदेश सरकार पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदेश के नायकों, महापुरूषों एवं आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी स्मृति को सजोने का कार्य कर रही है। इसके अलावा युवा पीढ़ी तक उनके त्याग एवं बलिदान की गाथा को पहुंचाने के लिए उपयुक्त स्थलों पर उनके स्मारक बनवाये जा रहे हैं। साथ ही उनकी प्रतिमा स्थापित कराकर उनके योगदान को स्मरण किया जा रहा है। देश पर अपने प्राण को न्यौछावर करने वाले राष्ट्रनायक हमारी गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं। नई पीढ़ी को इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में आजादी के शहीदों की एक लम्बी श्रृंखला है। प्रत्येक शहीद महापुरूषों ने अपने विभिन्न महान कार्यों से देश को आजाद कराने में योगदान दिया। यह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप देश को आजादी मिली। आज हम खुली हवा में सांस लेते हुए उनके योगदान को स्मरण कर रहे हैं। इन वीरों को कठोर सजाएं एवं यातनाएं दी गयी, इसके बावजूद उन्होंने मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। प्रदेश सरकार देश एवं प्रदेश के ऐसे वीरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनके स्मारक आदि का निर्माण करा रही है। साथ ही उनसे जुड़े स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराकर वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रही है। पर्यटन विभाग इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रहा है।

———————————

—केवल

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान बना आजमगढ़ में स्वरोजगार से स्वावलंबन का नया अध्याय

दिनांक : 10.09.2026

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से जनपद आजमगढ़ में युवाओं के स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तीकरण का एक नया परिदृश्य आकार ले रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ शुरू किया गया 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (सीएम युवा) जनपद के शिक्षित एवं हुनरमंद युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान का मूल ध्येय युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान कर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को गति देना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है।

जनपद आजमगढ़ में उद्यमशीलता को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के माध्यम से युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय स्वयं 'रोजगार प्रदाता' बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक लाख तथा आगामी एक दशक में दस लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य में आजमगढ़ अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह दूरदर्शी नीति न केवल जनपद की ग्रामीण प्रतिभाओं के महानगरों की ओर होने वाले आर्थिक पलायन को रोकने में मील का पत्थर साबित हो रही है, बल्कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने के व्यापक संकल्प में भी जनपदीय स्तर पर ठोस योगदान दे रही है।

योजना की पात्रता और स्वरूप को अत्यंत सरल, पारदर्शी एवं सर्वसमावेशी रखा गया है, जिससे जनपद आजमगढ़ का सामान्य पृष्ठभूमि का युवा भी बिना किसी प्रशासनिक बाधा के अपने उद्यम का सपना साकार कर सके। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे सभी स्थायी निवासी आवेदन के पात्र हैं, जिन्होंने न्यूनतम आठवीं कक्षा तक की औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर ली हो। योजना के अंतर्गत जनपद के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उनके तकनीकी हुनर को सीधे उत्पादक और लाभकारी इकाइयों में रूपांतरित किया जा सके।

उद्यम की स्थापना में आरंभिक वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए योजना में अत्यंत उदार वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यावसायिक फ्रेंचाइजी तथा 'बिजनेस ऑन व्हील्स' जैसी विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। योजना के प्रथम चरण में ₹5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए चार वर्षों की अवधि हेतु शत–प्रतिशत ब्याज–मुक्त और पूर्णतः गारंटी–मुक्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना की कुल लागत पर दस प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में वहन की जा रही है। सफल संचालन और समयबद्ध ऋण अदायगी के पश्चात उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए द्वितीय चरण में ₹10 लाख तक के वित्तीय पोषण की सुविधा भी दी जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में इस राज्यव्यापी अभियान का क्रियान्वयन अत्यंत सुनियोजित और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय संस्थाओं, अग्रणी बैंकों और संबंधित विभागों के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित कर योजना की पहुंच जनपद के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित की गई है। व्यापक जन–जागरूकता अभियानों और पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था के परिणामस्वरूप जनपद आजमगढ़ में अब तक लगभग छह हजार से अधिक युवाओं के ऋण प्रस्ताव बैंकों के स्तर से स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि जनपद में युवाओं के भीतर पनप रही उद्यमशीलता और स्वरोजगार के प्रति उनके बढ़ते विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

जनपद आजमगढ़ में योजना की धरातलीय सफलता और प्रभावशीलता का जीवंत उदाहरण मई खरगपुर (पोस्ट उबारपुर) के निवासी चंदन पाण्डेय के व्यावसायिक सफर के रूप में सामने आया है। परास्नातक स्तर की उच्च शिक्षा और डी. फार्मा की व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करने के बाद चंदन बेहतर भविष्य के लिए परंपरागत आजीविका और रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे थे। बाजार में सीमित अवसरों के बीच जब उन्हें जिला प्रशासन के सूचना माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी मिली, तो उन्होंने परावलंबन का मार्ग छोड़कर अपनी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के आधार पर स्वयं का उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया।

जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एकल खिड़की डिजिटल व्यवस्था का लाभ उठाते हुए चंदन पाण्डेय ने पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली और बैंकिंग तंत्र की तत्परता के चलते आवेदन की संवीक्षा से लेकर ऋण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया बेहद सहज और समयबद्ध ढंग से संपन्न हुई। बिना किसी व्यक्तिगत संपत्ति की गारंटी अथवा बंधक के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से उनके उद्यम के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ और उन्होंने अपने पैतृक क्षेत्र में ही आयुर्वेद आधारित उत्पादन इकाई की नींव रखी।

अभियान से प्राप्त वित्तीय सहायता और अनुदान का सदुपयोग करते हुए चंदन पाण्डेय ने 'वेदिका आयुर्वेद' ब्रांड के अंतर्गत आधुनिक प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना की। उन्होंने जनपद आजमगढ़ और आसपास के ग्रामीण अंचलों में सुलभ प्राकृतिक जड़ी–बूटियों एवं कृषि उपजों का उपयोग कर आयुर्वेदिक औषधियों और पोषक खाद्य उत्पादों के विनिर्माण की शुरुआत की। वर्तमान में उनकी विनिर्माण इकाई में आंवला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, पारंपरिक मुरब्बा, रसायन च्यवनप्राश तथा अन्य स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

उत्पादों की शुद्धता, प्रामाणिकता और प्रतिस्पर्धी मूल्य संरचना के चलते 'वेदिका आयुर्वेद' ने अत्यंत कम समय में स्थानीय उपभोक्ताओं और क्षेत्रीय बाजारों में अपनी अलग पहचान बना ली है। जनपद आजमगढ़ के स्थानीय बाजारों में इस ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में इस इकाई के बिक्री केंद्र पर प्रतिदिन औसतन 30 से 35 उपभोक्ता सीधे औषधियों एवं प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए पहुंचते हैं, जिससे इकाई को निरंतर कार्यशील पूंजी और आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त हो रही है।

वित्तीय दृष्टिकोण से चंदन पाण्डेय की यह इकाई जनपद स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक सफल मिसाल बन चुकी है। वर्तमान में इस सूक्ष्म उद्यम से प्रति माह लगभग ₹35,000 की नियमित आय अर्जित हो रही है, जिसमें समस्त परिचालन और उत्पादन लागतों को घटाने के बाद लगभग ₹25,000 की शुद्ध मासिक बचत हो रही है। इस इकाई का वार्षिक टर्नओवर चार से पांच लाख रुपये के स्तर तक पहुंच चुका है, जो ग्रामीण अंचल में स्थापित एक नई सूक्ष्म इकाई के लिए निरंतर विस्तार और दीर्घकालिक स्थायित्व का सशक्त संकेत है।

इस व्यावसायिक सफलता का सबसे उल्लेखनीय और प्रेरणादायी पहलू यह है कि यह प्रयास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जनपद के अन्य युवाओं के लिए आजीविका का द्वार भी खोला है। चंदन पाण्डेय ने अपनी निर्माण, पैकेजिंग और वितरण श्रृंखला में स्थानीय क्षेत्र के ही पांच युवाओं को नियमित सवेतन रोजगार से जोड़ा है। कल तक स्वयं रोजगार की तलाश में भटकने वाला एक ग्रामीण युवा आज प्रदेश सरकार की नीतिगत सहायता और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन से पांच परिवारों के आर्थिक संबल का आधार बन चुका है।

जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार की सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना से स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिल रहा है। कृषि एवं वानिकी आधारित कच्चा माल स्थानीय किसानों और संग्रहकर्ताओं से सीधे क्रय किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक पूंजी का संचार तीव्र हो रहा है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को अपने ही गृह जनपद में सम्मानजनक

कार्य मिलने से उनके भीतर सामाजिक सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना सुदृढ़ हो रही है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आज जनपद आजमगढ़ के युवाओं के लिए मात्र एक शासकीय वित्तीय योजना न रहकर उनके सपनों को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बन चुका है। जनपद के कोने–कोने में स्थापित हो रही ऐसी सूक्ष्म इकाइयां जहां स्थानीय प्रतिभा और श्रम का सदुपयोग कर रही हैं, वहीं वे जनपद के सामाजिक–आर्थिक ढांचे को भी नई गति प्रदान कर रही हैं।

——————————————————

सूचनाधिकारी जनपद आजमगढ़ /
डॉ0 सीमा गुप्ता (से0नि0 सहा0निदे0)